



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940  
No. 9] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSHA 17, 1940

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**  
**(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)**  
**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2019

**फा.सं. 16(35)/2018-एनईआर.**—स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दिनांक 21.12.2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार ने लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक इकाइयों के लिए “लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास योजना (एलएएनआईडीएस), 2018” अधिसूचित की है।

- योजना शीर्षक :-** इस योजना को “लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास स्कीम (एलएएनआईडीएस), 2018” कहा जाएगा।
- कवरेज:-** इस स्कीम के तहत “लक्षद्वीप” और “अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह” संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।
- शुरुआत तथा अवधि:-** यह 01.04.2018 से लागू होगी तथा 31.03.2020 तक पंजीकृत इकाइयों के लिए 31 मार्च 2025 तक प्राप्त प्रतिबद्ध दायित्वों सहित 31.03.2020 तक प्रभावी रहेगी।

**4. पात्रता:**

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की सभी नयी औद्योगिक इकाइयां और पर्याप्त विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाई उपक्रम इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।

- यह योजना **अनुबंध-1** में सूचीबद्ध उद्योगों के संबंध में लागू नहीं होगी।
- सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां इस योजना के एक अथवा अधिक घटकों से लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी, चाहे ऐसी इकाइयां भारत सरकार की अन्य स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हों। तथापि, यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक ही दावे की प्रतिपूर्ति दुबारा न हो।

4.3 इस योजना के सभी घटकों से होने वाले कुल लाभ, संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश की सीमा के अध्वधीन होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 200.00 करोड़ रुपए प्रति इकाई होगी। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण तथा सभी अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों की लागत शामिल होगी जो कि उस विशेष सेवा उद्योग के संचालन के लिए आधारभूत आवश्यकता है, लेकिन इसमें भूमि तथा उपभोज्य, डिसपोजेबल वस्तुओं अथवा राजस्व के लिए प्रभारित कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी। किसी विनिर्माण इकाई के लिए शामिल किए जाने/हटाए जाने वाले घटक **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

4.4 सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: -

- (क) पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्गठन से इसका निर्माण न हुआ हो।
- (ख) पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र या मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तांतरण से इसका निर्माण न हुआ हो।
- (ग) यह अन्यत्र से विस्थापित नहीं की गई हों और/अथवा यह पहले से मौजूद इकाई नहीं होनी चाहिए जिसे नए नाम एवं रूप के साथ पुनः खोला गया है।

## 5. परिभाषाएं

- (क) **“वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत”** से तात्पर्य है वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण की शुरुआत जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी का संस्थापन हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक गुणवत्ता में हर प्रकार से तैयार उत्पाद के विनिर्माण तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएं आदि उपलब्ध हों तथा यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुसार हों।
- (ख) **‘प्रभावी कदम’** से आशय, निम्नलिखित एक अथवा अधिक कदमों से है:-
  - (i) औद्योगिक इकाई के लिए जारी की गई पूंजी का 10% अथवा इससे अधिक का भुगतान किया जा चुका हो।
  - (ii) फैक्ट्री भवन के किसी हिस्से का निर्माण हो चुका हो।
  - (iii) औद्योगिक इकाई के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए फर्म आर्डर दिया जा चुका हो।
- (ग) **‘तैयार माल’** का अर्थ है वस्तुतः किसी औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित वह माल जिसके लिए वह पंजीकृत है।
- (घ) **‘औद्योगिक इकाई’** का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित इकाई के अलावा कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा क्षेत्र इकाई जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।
- (ङ) **‘विनिर्माण कार्य’** का अर्थ है वह कार्य जो निर्जीव भौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता है (i) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु, मद अथवा चीज का एक नये तथा विशिष्ट वस्तु अथवा मद अथवा चीज में कायान्तरण होता है जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है; अथवा (ii) जिससे एक अलग रासायनिक मिश्रण अथवा भिन्न ढांचे के साथ एक नयी तथा विशिष्ट वस्तु, मद अथवा चीज का निर्माण होता है।
- (च) **‘योग्य सेवा क्षेत्र इकाई’** सेवा क्षेत्र में एक उद्यम है, जिसमें काफी पूंजी व्यय की आवश्यकता है और इसमें अत्यधिक रोजगार सृजन क्षमता है।
- (छ) **‘नई औद्योगिक इकाई’** का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने अप्रैल, 2018 के पहले दिन अथवा इसके बाद परन्तु 31 मार्च, 2020 तक पंजीकरण कराया हो। ऐसी इकाइयों को पंजीकरण से 18 माह के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करना होगा।
- (ज) **‘मौजूदा औद्योगिक इकाई’** का अर्थ है एक औद्योगिक इकाई जिसने 01.04.2018 से पहले व्यावसायिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया है।
- (झ) **‘पर्याप्त विस्तार’** का अर्थ है क्षमता/आधुनिकीकरण के विस्तार के उद्देश्य से किसी मौजूदा औद्योगिक इकाई के संयंत्र और मशीनरी में निर्धारित पूंजी-निवेश में कम से कम 25% की वृद्धि।

(ज) 'भौतिक कार्यशील पूंजी' को फैक्ट्री द्वारा लेखा वर्ष के अंतिम दिवस को अपने स्वामित्व अथवा धारित अथवा नियंत्रणाधीन समस्त भौतिक माल सूचियों यथा सामग्रियां, ईंधन एवं स्नेहक, भंडारण आदि जिसका इस्तेमाल स्वयं फैक्ट्री द्वारा विनिर्मित उत्पाद में अथवा प्रसंस्करण हेतु अन्य को फैक्ट्री द्वारा आपूरित उत्पाद में इस्तेमाल होता है, को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। भौतिक कार्यशील पूंजी में सामग्री भंडार, ईंधन एवं अन्य भंडार आदि, जिसे स्पष्ट तौर पर पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया हो, अर्द्ध-तैयार माल तथा अन्यो को प्रगति पर कार्य तथा फैक्ट्री द्वारा बनाया गया माल जो लेखा वर्ष के अंत में बिक्री के लिए तैयार हो, शामिल है। तथापि, इसमें प्रसंस्करण हेतु अन्यो द्वारा फैक्ट्री को आपूरित सामग्री भंडार, ईंधन, भंडार आदि शामिल नहीं है। फैक्ट्री द्वारा आपूरित कच्चे माल से अन्यो द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल तथा उनके द्वारा धारित माल को शामिल किया गया है तथा अन्यो द्वारा आपूरित कच्चे माल से फैक्ट्री द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल को शामिल नहीं किया गया है।

(ट) 'कच्चा माल' का अर्थ है तैयार माल के विनिर्माण में किसी औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुतः अपेक्षित तथा इस्तेमाल किया गया कच्चा माल जिसके लिए अनुरोध किया गया है।

(ठ) 'कार्यशील पूंजी' उपर्युक्त पैरा (झ) में यथापरिभाषित भौतिक कार्यशील पूंजी तथा हस्तगत नकदी तथा बैंक में जमा तथा लेखा वर्ष के अंत में देय राशि पर प्राप्य राशि के निवल शेष की कुल राशि है।

तथापि, अन्य अप्रयुक्त ओवर ड्राफ्ट सुविधा, समयावधि पर ध्यान दिए बिना मियादी जमा, स्थिर परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए अग्रिमों, ऋणों तथा स्वामियों एवं भागीदारों द्वारा उनके प्रयोजन एवं समयावधि पर ध्यान दिए बिना अग्रिम, ब्याज सहित दीर्घावधि ऋणों तथा निवेशों को कार्यशील पूंजी से बाहर रखा गया है।

(ड) 'संयंत्र और मशीनरी' में स्थल पर स्थापित नए खरीदे गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होंगे। अनुबंध-II में दिए गए योजना के घटकों तहत अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफर्बिश्ड संयंत्र और मशीनरी इस सहायता के पात्र नहीं हैं। मशीनरी की खरीद सामान्य मूल्य पर खुले बाजार से की जानी चाहिए। उसके दावे को मंजूर करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या यह खरीद किसी संबंधित पक्ष से की गई है अथवा नजदीकी प्राप्य मूल्य प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना की गई है।

6. इस योजना के अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कुल प्रोत्साहन, 200 करोड़ रुपये प्रति इकाई की अधिकतम सीमा के अध्येधीन संयंत्र एवं मशीनरी के कुल निवेश से अधिक नहीं होने चाहिए। पात्र औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

1. ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)
2. केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई)
3. केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई)
4. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति
5. आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति
6. परिवहन प्रोत्साहन (टीआई); तथा
7. रोजगार प्रोत्साहन (ईआई)

### 6.1 ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)

6.1(क) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की कहीं पर भी अवस्थित सभी पात्र नयी औद्योगिक इकाइयों को ऋण के लिए (सीसीआईआईएसी) 5.00 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में पात्र निवेश के 30% के हिसाब से केंद्रीय पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

6.1 (ख) गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सहायता प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने से पहले किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना लागत का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। कुल सहायता की विशिष्ट सम्पूर्ण राशि को सरकारी मंजूरी में दर्शाया जाएगा।

6.1 (ग) सरकार की, लागत के बढ़ने के मामले में सहायता राशि बढ़ाने की कोई वचनबद्धता नहीं है। परियोजना के समय-पूर्व बंद करने अथवा बीच में ही छोड़े जाने की अवस्था में सरकार द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण सहायता को गृह मंत्रालय को लौटानी होगी।

## 6.2 केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई)

6.2 (क) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कहीं पर भी अवस्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को इनके वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की तारीख से प्रथम 5 वर्षों तक अनुसूचित बैंकों अथवा केंद्रीय/ राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अग्रिम कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% के हिसाब से ब्याज प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस प्रोत्साहन को इस तरह प्रतिबंधित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋणदाता संस्था के फंड आधारित ऋण-दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत से प्रोत्साहन कृत ब्याज-दर कम नहीं हो।

6.2 (ख) इस योजना के प्रयोजनार्थ किसी इकाई की कार्यशील पूंजी अपेक्षा को उनके वार्षिक कारोबार के 25% तक सीमाबद्ध किया जाएगा। उपर्युक्त अधिकतम स्तर की व्यवस्था हो जाने के बाद माल सूची मानदंड यदि आवश्यक हो, लागू हो सकते हैं। ऐसी इकाइयों जिनके लिए मानदंड निर्धारित/लागू नहीं हैं, के संबंध में कार्यशील पूंजी संबंधी अनुरोध पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यशील पूंजी के उक्त अधिकतम स्तर से अधिक नहीं होने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए। माल-सूची तथा प्राप्ति के लिए विशेष मानदंड भी बनाए जा सकते हैं।

## 6.3 केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई)

6.3 (क) लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कहीं पर अवस्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए भवन परिसरों तथा संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

6.3 (ख) बीमा प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ, औद्योगिक इकाई का अर्थ है कोई उद्योग जो अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार अग्नि नीति 'ग' में शामिल है। यह नीति प्रस्तावक द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर बीमा कंपनी द्वारा जारी की जाएगी।

## 6.4 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कहीं पर अवस्थित सभी नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां, निम्नलिखित शर्त के अध्याधीन, वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए सीजीएसटी तथा आईजीएसटी में केंद्रीय हिस्से की सीमा तक विनिर्मित तैयार उत्पादों पर भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी:

तैयार वस्तुओं पर जीएसटी प्रतिपूर्ति, निविष्टि कर ऋण नियमावली (इनपुट टैक्स क्रेडिट रूलस), 2017 के अंतर्गत निविष्टि कर ऋण के उपयोग के माध्यम से भुगतान किए गए कर राशि को छोड़कर, सिर्फ भुगतान किए गए निवल जीएसटी पर ही लागू है।

तदनुसार, प्रतिपूर्ति\* की गई जीएसटी राशि निम्नलिखित का कुल योग होगा:

(क) केंद्रीय कर तथा एकीकृत कर के निविष्टि कर ऋण के उपयोग के पश्चात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उप-धारा (1) के अनुसार इकाई द्वारा रखे जाने वाले नकद लेजर लेखा में डेबिट के माध्यम से भुगतान किए गए केंद्रीय कर का 58%।

(ख) केंद्रीय कर तथा एकीकृत कर के निविष्टि कर ऋण टैक्स के उपयोग के पश्चात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 20 के अनुसार इकाई द्वारा रखे जाने वाले नकद लेजर लेखा में डेबिट के माध्यम से भुगतान किए गए एकीकृत कर का 29%।

जहां निविष्टि को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 10 के तहत कंपोजीशन योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त किया गया है, राशि अर्थात्, उपर्युक्त (क) तथा (ख) के कुल योग को प्राप्त निविष्टि के कुल मूल्य में से कंपोजीशन योजना के अंतर्गत प्राप्त निविष्टियों के समान प्रतिशत मूल्य से घटा दिया जाएगा।

**नोट:** प्रतिपूर्ति के इस प्रतिशत में परिवर्तन वित्त आयोग द्वारा राज्यों को जारी वित्त वितरण में परिवर्तन के अनुरूप होगा।

### 6.5 आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति

इस योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाई पहले 5 वर्षों के लिए आयकर के केंद्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है, जिसमें इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का वर्ष भी शामिल है।

### 6.6 परिवहन प्रोत्साहन (टीआई)

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित सभी पात्र नयी औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार वाली मौजूदा इकाइयां रेल अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के रेल उपक्रम, आंतरिक जल-मार्ग अथवा निर्धारित एयरलाइन के माध्यम से केवल तैयार माल के परिवहन पर वास्तविक रसीदों की प्रस्तुति के अध्यक्षीन वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के 5 वर्ष की अवधि के लिए परिवहन प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है। विभिन्न साधनों के जरिए परिवहन प्रोत्साहन संबंधी शर्तें एवं निबंधन निम्नानुसार हैं:

- (क) औद्योगिक इकाई की अवस्थिति के निकटतम पत्तन (पोर्ट) से मुख्य भूमि पत्तन तक सीधे या द्वीप के मुख्य पत्तन के माध्यम से तैयार माल के परिवहन लागत के 20% तक।
- (ख) मुख्य भूमि पत्तन के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन से क्रेता के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन तक रेल द्वारा तैयार माल के परिचालन के लिए रेलवे या रेलवे पीएसयू द्वारा वर्तमान में दिए जाने वाले प्रोत्साहन सहित परिवहन लागत का 20%।
- (ग) औद्योगिक इकाई के स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से देश में क्रेता के निकटतम किसी भी हवाई अड्डे तक खराब होने वाली वस्तुओं (आईएटीए द्वारा यथापरिभाषित) के लिए निर्धारित एयरलाइंस एवं डीजीसीए द्वारा अनुमोदित गैर-अनुसूचित प्रचालक (एनएसओपी) परमिटधारकों द्वारा वायुमार्ग मालभाड़े संबंधी लागत का 33%।

### 6.7 रोजगार प्रोत्साहन (ईआई)

गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान जिसे सरकार वहन करती है के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के अतिरिक्त 3.67% अंशदान का भुगतान किया जाएगा।

**6.8** यह लाभ प्रतिपूर्ति के आधार पर दिया जाएगा।

## 7. उच्चाधिकार प्राप्त समिति

7.1 एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी जिसके अध्यक्ष सचिव, गृह मंत्रालय तथा इसमें औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, व्यय विभाग, नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा उस उद्योग के मामले से जुड़े भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव तथा लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र जहां पर इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु प्रोत्साहन का दावा करने वाली लाभार्थी इकाई अवस्थित है, के संबंधित मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग) शामिल होंगे। प्रोत्साहनों के प्रस्तावों की जांच करते समय लागत पहलू, परियोजना व्यवहार्यता, बैंक योग्यता, रोजगार सृजन तथा प्रोत्साहन प्रदाता जोखिम पूंजी जैसे कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अंतर्गत आने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7.2 पंजीकरण/सिद्धांततः अनुमोदन के संबंध में इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाई की प्राथमिक पात्रता, बजट की उपलब्धता पर विचार करेगी तथा इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्रता का निर्णय करेगी। कोई भी औद्योगिक इकाई एलएनआईडीएस के अंतर्गत पंजीकरण अथवा लाभों का

दावा करने का हक नहीं रख सकेगी बशर्ते कि यह केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित हो। प्रोत्साहन के भुगतान में विलम्ब की वजह को लेकर किसी प्रकार के ब्याज का किसी इकाई द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकता। इस योजना के लाभार्थी को इस योजना के शर्त तथा निबंधन का अनुपालन करने का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## 8. ऑनलाइन पंजीकरण

8.1 इस योजना में इस बात की आवश्यकता है कि सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में इस योजना में इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए पात्र होने हेतु पहले से ही पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करवाना होगा। इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत आवेदकों को डीपीआर के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

8.2 गृह मंत्रालय एलएएनआईडीएस के लिए ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग करने के और पात्र इकाइयों के पंजीकरण के विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी करेगा।

## 9. वाणिज्यिक उत्पादन

9.1 इन इकाइयों को अनुमोदन के 18 महीनों में वाणिज्यिक उत्पादन आवश्यक रूप से शुरू कर देना चाहिए।

## 10. नोडल एजेंसी

10.1 द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) इस योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के संवितरण हेतु एक नोडल एजेंसी होगी। द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) केवल पात्र औद्योगिक इकाइयों के नामित बैंक खातों में ई-ट्रांसफर के जरिए प्रोत्साहन जारी करेगा।

## 11. दावों की जांच प्रक्रिया

11.1 गृह मंत्रालय में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन तथा परिवहन प्रोत्साहन के अंतर्गत प्रोत्साहन के दावों की एक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र लेखा-परीक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व-जांच की जाएगी। द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) हर बार जारी किए गए दावों के 10% की लेखा परीक्षा पश्चात जांच करेगा। गृह मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जारी किए गए प्रोत्साहन दावों के 20% की लेखा परीक्षा करेंगे।

11.2 सरकार के पास इस योजना के किसी भी भाग में जनहित में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

11.3 इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करने तथा आवश्यक अनुदेश जारी करने की आवश्यकता होगी।

## 12. केंद्र/संघ राज्य प्रशासन/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार

12.1 यदि केंद्रीय सरकार/संघ राज्य प्रशासन/संबंधित वित्तीय संस्था को इस बात की पुष्टि हो कि किसी औद्योगिक इकाई ने आवश्यक तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत कर या जाली सूचना देकर धोखे से प्रोत्साहन प्राप्त किया है, अथवा यदि यह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन के शुरू होने के बाद 5 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन बंद कर देती है तो केंद्रीय सरकार/ संघ राज्य प्रशासन / द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) उस इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अनुदान अथवा प्रोत्साहन लौटाने के लिए कह सकते हैं। यह प्रोत्साहन डिजिटल भुगतान के जरिए जारी किये जाएंगे तथा द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप) लाभार्थी औद्योगिक इकाइयों के संबंध में डीबीटी मिशन द्वारा अपेक्षित सभी सूचना एकत्रित करेगा। द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) लाभार्थी इकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से इस संबंध में एक शपथपत्र ले सकता है। योजना की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली लाभार्थी इकाई को प्रोत्साहन के वितरण से पूर्व औद्योगिक इकाई और द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) के बीच एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर भी हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

12.2 दी गई सूचना को जान-बूझ कर छुपाने अथवा तीसरे पक्ष के जरिए धोखा करने अथवा गैर- द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) उत्पादन के लिए दावा करने अथवा इसी प्रकार के कदाचार करने पर औद्योगिक इकाई के भावी दावे जब्त कर लिए जाएंगे तथा पूर्व में दिए गए सभी प्रोत्साहनों की वसूली 15% वार्षिक ब्याज की दर से की जाएगी।

12.3 गृह मंत्रालय /संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्था के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी औद्योगिक इकाई के स्वामी को आंशिक अथवा समग्र प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद किसी औद्योगिक इकाई के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई को परिवर्तित करने अथवा इकाई का आकार कम करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के अंदर इसके कुल तय पूंजी निवेश के बड़े हिस्से को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इकाई द्वारा स्थल अथवा संपर्क सूत्र में किसी परिवर्तन के संबंध में गृह मंत्रालय को सूचित करना भी अपेक्षित है।

12.4 उन सभी इकाइयों को जिनको द्वीप समूह प्रशासन (अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप) द्वारा प्रोत्साहन वितरित किया गया है, दिए गए आशय हेतु सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रपत्र 12 (ग) में प्रोत्साहन (प्रोत्साहनों) के इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र गृह मंत्रालय को संबंधित वित्तीय संस्था/संघ राज्य प्रशासन द्वारा अंतिम किश्त/पूर्ण राशि प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

12.5 प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक औद्योगिक इकाई को गृह मंत्रालय /संबंधित संघ राज्य प्रशासन को उत्पादन के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन जारी रखने के संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करनी होगी।

### 13. बजटीय शीर्ष

13.1 इस योजना हेतु बजट गृह मंत्रालय द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों संबंधी अनुदान मांगों के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उनके द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए।

14. इसे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

### अनुबंध-I

#### निषेध-सूची

एलएनआईडीएस, 2018 के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।

- (i) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से संबंधित हैं।
- (ii) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अंतर्गत आने वाले पान मसाला
- (iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 705(अ), दिनांक 02.09.1999 तथा का.आ. 698(अ), दिनांक 17.06.2003 के अंतर्गत विशिष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियां।
- (iv) पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला सामान।
- (v) पौधरोपण, शोधशालाएं तथा 10 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन इकाइयां।
- (vi) कोक (कैल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), प्लाई ऐश, सीमेंट, स्टील रोलिंग मिल।
- (vii) पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईए) अथवा संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाइयां इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगी।

- (viii) उच्च कीमत के पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर भंडारण के दौरान संरक्षण, साफ-सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लैबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य आदि में परिवर्तन जैसे कम मूल्य संवर्धन कार्यकलापों की अनुमति होगी।
- (ix) सरकार द्वारा कभी भी आवश्यक समझे जाने पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से निषेध सूची में शामिल कोई अन्य उद्योग/कार्य। यह ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।
- (x) गोल्ड और गोल्ड डोर।

### अनुबंध-II

#### क. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु शामिल किए जाने वाले घटक:

- (i) कर और शुल्क सहित औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी की लागत अर्थात् विनिर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उत्पादन उपकरण की लागत
- (ii) उत्पादक उपकरण जैसे टूल्स, जिग्स, डाई और मोल्ड, इन्श्योरेंस प्रीमियम आदि की कर और शुल्क सहित लागत
- (iii) संयंत्र की और जहां मीटर लगाया गया है, से तैयार वस्तुओं के उत्पादन/डिस्पैच वाले स्थान तक संयंत्र के प्रचालन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रिकल घटक (अर्थात् एच.टी. मोटर, एल.टी. मोटर, स्विच बोर्ड, पैनल, कैपेसिटर, रिले, सर्किट ब्रेकर, पैनल बोर्ड, स्विच गियर)
- (iv) आपूर्तिकर्ता के परिसर से इकाई के स्थान तक संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण लाने के लिए भुगतान किया गया मालभाड़ा
- (v) भुगतान किया गया ट्रांजिट इन्श्योरेंस प्रीमियम
- (vi) उस स्थान तक माल को ढोने में निवेश की गई राशि जहां कच्चे माल के परिवहन और तैयार माल के विपणन के लिए उसका उपयोग किया गया

#### ख. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु निम्नलिखित घटकों को शामिल नहीं किया जाएगा:

- (i) माल चढ़ाने और उतारने का भाड़ा
- (ii) संयंत्र और मशीनरी के लिए शेड/भवन
- (iii) डीजी सेट, उत्खनन/खनन संबंधी उपकरण, हैंडलिंग उपकरण, ऊपर क (iii) में जिनका उल्लेख किया गया है, उन्हें छोड़कर अन्य इलेक्ट्रिकल घटकों जैसे विविध नियत परिसंपत्तियां
- (iv) कच्चे माल और अन्य उपभोज्य भण्डारों सहित कार्यशील पूंजी
- (v) चालू करने संबंधी लागत
- (vi) कैपिटल पावर प्लांट
- (vii) भण्डारण उपकरण
- (viii) वजन तोलने का उपकरण (वेट ब्रिज), प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण

#### ग. विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन एवं स्थापना संबंधी प्रभार की स्वीकार्यता

उत्पादन एवं स्थापना संबंधी प्रभार का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा और औद्योगिक इकाई को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन टिप्पणी में निर्धारित लागत तक सीमित होगा।



**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Industrial Policy & Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2019

**F.No.16(35)/2018-NER.**—In pursuance of the decision taken by the Standing Finance Committee (SFC) in its meeting held on 21.12.2018, the Government of India hereby notifies the “Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands Industrial Development Scheme, (LANIDS) 2018 for industrial units in Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands.

**1. Scheme title:** - The scheme will be called “Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands Industrial Development Scheme, (LANIDS) 2018”.

**2. Coverage:** - The scheme will cover Union Territories of “Lakshadweep” and “Andaman & Nicobar Islands”.

**3. Commencement and duration:** - It will be effective from 01.04.2018 and will remain in force up to 31.03.2020 with committed liabilities accrued up to 31<sup>st</sup> March 2025 for units registered up to 31.03.2020.

**4. Eligibility:**

**4.1** Unless otherwise specified, all new industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion in manufacturing and services sectors located in the Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands, will be eligible for incentives under the scheme.

**4.2** The scheme shall not be applicable to the industries listed in the **Annexure – I**.

**4.3** All eligible industrial units will be entitled to benefits under one or more components of this scheme, even if such units are getting benefits under other schemes of the Government of India. However, it shall be ensured that there is no duplicacy in the reimbursement of the same claims under different schemes.

**4.4** The total benefits from all components of the scheme put together shall be limited to the total investment in plant and machinery, subject to a maximum limit of Rs.200.00 crore per unit. Plant and Machinery for the service sector industrial units shall include cost of construction of building and all other durable physical assets basic to the running of that particular service industry, but shall exclude cost of land and consumables, disposables or any other item charged to revenue. Components to be included / excluded for a manufacturing unit are at **Annexure II**.

**4.5** All eligible industrial units will be required to fulfil the following conditions:-

- (a) it is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.
- (b) it is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose.
- (c) it has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.

**5. Definitions**

(a) ‘**Commencement of Commercial Production**’ means starting of manufacture of finished products on commercial scale which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery and on that day the plant must be ready in all respects for manufacture of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available and as per date of registration with Central Excise/Goods and Services Tax (GST) authorities.

(b) ‘**Effective steps**’ means one or more of the following steps:-

- (i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up.
- (ii) that any part of the factory building has been constructed.
- (iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.

(c) ‘**Finished Goods**’ means the goods actually produced by an industrial unit and for which it is registered.

(d) ‘**Industrial Unit**’ means any industrial undertaking or eligible service sector unit, other than that run departmentally by Government, which is a registered business enterprise under Goods & Services Tax.

- (e) **‘Manufacturing Activity’** means “an activity which brings about a change in non-living physical object or article or thing (i) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (ii) bringing into existence of a new and distinct object, article or thing with a different chemical composition or integral structure”.
- (f) **‘Eligible Service Sector Unit’** is an enterprise in the services sector that requires significant capital expenditure and has significant employment generation potential.
- (g) **‘New industrial unit’** means an industrial unit which registers itself on MHA portal on or after the first day of April, 2018 but not later than 31<sup>st</sup> day of March, 2020. Such units have to commence commercial production/ operation within 18 months of registration.
- (h) **‘Existing Industrial unit’** means an industrial unit which commences commercial production/ operation before 01.04.2018.
- (i) **‘Substantial Expansion’** means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in Plant & Machinery of an existing industrial unit for purpose of expansion of capacity / modernization.
- (j) **‘Physical Working Capital’** is defined to include all physical inventories owned, held or controlled by the factory as on the closing day of the accounting year such as the materials, fuels & lubricants, stores etc., that enter into products manufactured by the factory itself or supplied by the factory to other for processing. Physical working capital also includes the stock of materials, fuels & stores etc., purchased expressly for re-sale, semi-finished goods and work in progress on account of others and goods made by the factory which are ready for sale at the end of the accounting year. However, it does not include the stock of the materials, fuels, stores etc. supplied by others to the factory for processing. Finished goods processed by others from raw materials supplied by the factory and held by them are included and finished goods processed by the factory from raw materials supplied by others are excluded.
- (k) **‘Raw Material’** means any raw material actually required and used by an industrial unit in manufacturing of the finished goods for which it is requested.
- (l) **‘Working Capital’** is the sum total of the physical working capital as defined in Para (i) above and the cash deposits in hand and at bank and the net balance of amounts receivable over amounts payable at the end of the accounting year.
- Working capital, however, excludes unused overdraft facility, fixed deposits irrespective of duration, advances for acquisition of fixed assets, loans and advances by proprietors and partners irrespective of their purpose and duration, long term loans including interest thereon and investments.
- (m) **‘Plant and Machinery’** shall cover the cost of newly purchased industrial plant and machinery as erected at site. Relocated / Recycled / Refurbished plant and machinery is not eligible for assistance under the Scheme. The purchase of machinery should be from open market at normal market price. It will be ascertained whether the purchase has been made from a Related Party or without following an arms-length price discovery, before sanctioning the claim thereof.

6. The total incentives availed by an eligible industrial unit under the scheme should not exceed the total investment in plant and machinery, subject to a maximum limit of Rs. 200.00 crores per unit. The following incentives will be provided to eligible industrial units on reimbursement basis:

1. Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)
2. Central Interest Incentive (CII)
3. Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)
4. Goods and Services Tax (GST) Reimbursement
5. Income Tax (IT) Reimbursement
6. Transport Incentive (TI); and
7. Employment Incentive (EI)

### 6.1 Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)

6.1(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion in the manufacturing and service sector located anywhere in the Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands will be provided Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC) @ 30% of the investment in plant and machinery with an upper limit of Rs.5.00 crore.

6.1(b) The project cost will need to be appraised by a Scheduled Commercial Bank or Financial Institution before the proposal of assistance is approved by the Empowered Committee of MHA . The specific absolute amount of total assistance shall be indicated in the government sanction.

6.1(c) The government does not commit itself to increase in the scale of assistance in case of cost escalation. In case the project is foreclosed or abandoned midway the entire assistance released by government will be refunded to MHA.

### 6.2 Central Interest Incentive (CII)

6.2(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands shall be given an interest incentive @3% on working capital credit advanced by the Scheduled Banks or Central/State financial institutions for first 5 years from the date of commencement of commercial production/ operation. The incentive will be so restricted as to ensure that subsidized interest rate is not below the Marginal Cost of funds based Lending Rates (MCLR) of the lending institution.

6.2(b) For the purpose of this Scheme, the working capital requirement of a unit shall be capped at @ 25 % of their annual turnover. Inventory norms may be applied, if necessary, after providing for aforesaid maximum level. In respect of such units for which norms have not been laid down/ are not applicable, the request of working capital should be considered favorably by the Empowered Committee so long as the working capital is not very much above such maximum level. Special norms can also be evolved for inventory and receivables.

### 6.3 Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

6.3(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands will be eligible for reimbursement of 100% insurance premium on insurance of building and Plant & Machinery for a maximum period of 5 years from the date of commencement of commercial production/ operation.

6.3(b) For the purpose of insurance incentive, Industrial Unit shall mean any industry which is included in Fire Policy 'C' as per All India Fire Tariffs. The policy shall be issued by the Insurance Company on market valuation to be declared by the proposer.

### 6.4 Goods and Services Tax (GST) Reimbursement

All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands shall be eligible for reimbursement of Goods and Services Tax (GST) paid on finished products manufactured up to the extent of central share of the CGST and IGST for period of 5 years from the date of commencement of commercial production subject to the following condition:

GST reimbursement on finished goods is applicable only on the net GST paid, other than the amount of Tax paid by utilization of Input Tax credit under the Input Tax Credit Rules, 2017.

Accordingly, the amount of GST reimbursed\* shall be a sum total of:

(a) 58% of the Central tax paid through debit in the cash ledger account maintained by the unit in terms of sub-section(1) of section 49 of the Central Goods and Services Act, 2017 after utilization of the Input tax credit of the Central Tax and Integrated Tax.

(b) 29% of the integrated tax paid through debit in cash ledger account maintained by the unit in terms of section 20 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 after utilization of the Input tax credit Tax of the Central Tax and Integrated Tax

Provided where inputs are procured from a registered person operating under the Composition Scheme under section 10 of the Central Goods and Services Act, 2017, the amount i.e., sum total of (a) & (b) above shall be reduced by the same percentage value of inputs procured under Composition scheme out of total value of inputs procured.

\*Note: This percentage of reimbursement shall be changed as per the change in devolution of finances to the States by the Finance Commission.

**6.5. Income Tax (IT) Reimbursement**

The industrial unit set up under this scheme can claim reimbursement of central share of income tax for first 5 years, including the year of commencement of commercial production by the unit.

**6.6. Transport Incentive (TI)**

All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands can avail incentive on Transportation of only finished goods through shipping, railways or the railway public sector undertaking, inland waterways or scheduled airlines for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production / operation, subject to production of actual receipt. The terms and conditions of transport incentive through different modes are as follows:-

- (a) Up to 20% of the cost of transportation for finished goods for shipping from the port nearest to the location of the industrial unit to the mainland port directly, or via the main port of the island.
- (b) 20% of the cost of transportation including the incentive currently provided by railways or the Railway PSUs for movement of finished goods by rail from the railway station nearest to the mainland port to the railway station nearest to the location of the buyer.
- (c) 33% of the cost of transportation of Air Freight by scheduled airlines and non-scheduled operator permit (NSOP) holders approved by DGCA for perishable items / goods (as defined by IATA) from the airport nearest to the location of industrial unit to any airport within the country, nearest to the location of the buyer.

**6.7. Employment Incentive (EI)**

MHA shall be paying additional 3.67% of the employer's contribution to Employees' Provident Fund (EPF) in addition to Government bearing 8.33 % Employee Pension Scheme (EPS) contribution of the employer in the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY).

**6.8.** The benefits shall be given on the basis of reimbursement.

**7. Empowered Committee**

**7.1** There will be an Empowered Committee chaired by Secretary, Ministry of Home Affairs with representatives from DIPP, D/o Expenditure, NITI Aayog and Secretary of the concerned Ministries/Departments of Government of India dealing with the subject matter of that industry, the concerned Chief Secretary/ Secretary (Industry) of the UT Administration of the Lakshadweep Islands and Andaman & Nicobar Islands where the beneficiary unit claiming incentive is located, as members, for selection of beneficiaries under the scheme. While examining the proposals for incentive, due consideration will be given to factors like cost disadvantage, project viability, bankability, employment generation and promoters' risk capital. Preference will also be given to eligible industrial units under the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

**7.2** The final grant of registration/ in-principle approval will be decided by the Empowered Committee, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the industrial unit, availability of budget and decide the eligibility for registration under the Scheme. No Industrial unit will have the right to register under LANIDS or claim the benefits unless it is specifically approved by the Central Government. No interest on account of delay in payment of incentive can be claimed by the unit. The beneficiary of this Scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the Scheme

**8. Online Registration**

**8.1** The Scheme requires that all eligible industrial units would have to register under the Scheme with Ministry of Home Affairs, Govt. of India, through the portal prior to being eligible for any benefit under this scheme. In this regard, an online application process shall be developed under which the applicants have to submit applications along with the DPR.

**8.2** The MHA would separately issue detailed instructions for the use of online portal for LANIDS and registration of eligible units.

**9. Commercial Production**

**9.1** The units should mandatorily start commercial production within 18 months of approval.

**10. Nodal agency**

10.1 The Islands Administration (A&N or Lakshadweep) will be the nodal agency for disbursement of incentives under various components of the Scheme. Islands Administration (A&N or Lakshadweep) will release incentive only through e-transfer to designated bank accounts of the eligible industrial units.

**11. Process of Scrutiny of claims**

11.1 Incentive claims under Capital Investment Incentive and Transport Incentive received in MHA will be pre-scrutinized by a recognized independent audit agency. Islands Administration (A&N or Lakshadweep) will conduct post-audit of 10% of claims released every time. The Chief Controller of Accounts of MHA will also conduct post-audit of 20% of incentive claims released in each financial year.

11.2 Government reserves the right to modify any part of the Scheme in public interest.

11.3 All concerned Ministries/Department of Government of India are required to amend their respective Acts/Rules/ Notification etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions.

**12. Rights of the Centre/ UT Administration/ Financial Institutions**

12.1 If the Central Government/ UT Administration/ Financial Institution concerned is satisfied that an industrial unit has obtained incentive(s) by misrepresenting an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production/ operation within 5 years after commencement of commercial production/ operation, the Central Government/ Union Territories / Islands Administration (A&N or Lakshadweep) may ask the unit to refund the grant or incentive after giving an opportunity of being heard to the unit. The incentive(s) will be released through digital payment and Islands Administration (A&N or Lakshadweep) would collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary industrial units. Islands Administration (A&N or Lakshadweep) may take an affidavit in this regard from authorized signatory of the beneficiary unit. An indemnity bond may also be signed between the industrial unit and Islands Administration (A&N or Lakshadweep) prior to disbursement of incentives, providing for undertaking on the part of the beneficiary unit to comply with all the requirements of the scheme.

12.2 Concealment of input supplies or routing of third party or non- Islands Administration (A&N or Lakshadweep) production for claims or malpractices of similar kinds will render the industrial unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous subsidies with interest @ 15% per annum.

12.3 Without taking prior approval of MHA/State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the incentive will be allowed to change the ownership of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production. The unit will also be required to keep MHA informed about change in location or contact information.

12.4 In respect of all units to whom the incentive is disbursed by Islands Administration (A&N or Lakshadweep), certificate of utilization of the incentive(s) in Form 12(C) of General Financial Rules, 2017 for the purpose for which it was given shall be furnished to the MHA by the financial institution/UT Administration concerned, within a period of three months from the date of receipt of the last installment/full amount.

12.5 After receiving the incentive(s), each industrial unit shall submit Annual Progress Report (APR) to the MHA/ UT Administration concerned, about its working for a period of 5 years after going into production.

**13. Budgetary Head**

13.1 The budget for the scheme should be made available and administered by Ministry of Home Affairs under the Demands for Grants of the respective Union Territory.

14. This issues with approval of Hon'ble Commerce and Industry Minister.

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

**Annexure – I****Negative List:**

The following industries will not be eligible for benefits under LANIDS, 2018.

- (i) All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
- (ii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
- (iii) Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705 (E) dated 02.09.1999 and S.O. 698 (E) dated 17.6.2003.
- (iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
- (v) Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.
- (vi) Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash, Cement, Steel Rolling Mills.
- (vii) Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for incentive under the scheme.
- (viii) Low value addition activities like preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.
- (ix) Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification.
- (x) Gold and gold dore.

**Annexure-II****A. Components to be included for computing the value of Plant and Machinery under CCIAC in the manufacturing sector:**

- (i) Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.
- (ii) Cost of Productive equipment such as tools, jigs, dyes and moulds, insurance premium etc. including taxes and duties.
- (iii) Electrical components necessary for plant operation on the plant side from where meter is installed up to the point where finished goods is to be produced/ dispatched (i.e. H.T. Motors, L.T. Motors, Switch Boards, Panels, Capacitors, Relay, Circuit Breakers, Panel Boards, Switchgears).
- (iv) Freight charges paid for bringing Plant & Machinery and equipment from the supplier's premises to the location of the unit.
- (v) Transit Insurance premium paid.
- (vi) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilized for transport of raw materials and marketing of the finished products.

**B. Components which will not be considered for computing the value of Plant & Machinery under CCIAC in the manufacturing sector:**

- (i) Loading and unloading charges
- (ii) Sheds/ buildings for Plant & Machinery
- (iii) Miscellaneous fixed assets such as DG sets, Excavation/ Mining equipments, handling equipments, electrical components other than those mentioned at A (iii) above.

- (iv) Working Capital including Raw Material and other consumable stores.
- (v) Commissioning cost
- (vi) Captive Power Plants
- (vii) Storage equipments
- (viii) Weigh bridge, Laboratory testing equipment.

**C. Admissibility of erection and installation charges in the manufacturing sector**

Erection and installation charges will be payable on actual basis and will be restricted to the cost indicated in the Appraisal Note of the Financial Institutions which provided loan to the industrial unit.